दो शीर्ष भारतीय जिन्हें जेल में होना चाहिये : नवीन जिंदल और राबर्ट वाड्रा

नवीन जिंदल ने झारखंड में हज़ारों एकड़ लैह- अयस्क खदानें इस आधार पर सरकार से लीज़ पर ली थीं कि इस्पात काारखाने लगेंगे जिनसे सरकार को राजस्व और जनता को रोज़गार मिलेगा। जाहिर है ऐसे नेक काम के लिये ज़मीनें कौड़ियों के मोल मिल जाती हैं। पर बरसों से इन खदानों का ऐसा भयानक दोहन चल रहा है कि किसी की भी आत्मा कांप उठे।

इस्पात प्लांट तो जिंदल ने क्या लगाना था, क्योंकि भारी भरकम निवेश लगाने के बावजूद मुनाफ़ा कम और देर से आता है। लिहाजा इस आड़ में रोज़ाना हज़ारों ट्रक लौह अयस्क निकाल कर समुन्द्र के रास्ते चीन भेजा जा रहा है। यह वही तरीका-ए-वारदात है जो कुख्यात रेड्डी बंधुओं ने कर्नाटका व आंध्रा में लोहे एवं कोयले की तस्करी के माध्यम से लाखों करोड़ की लूट डकारने के लिये अपनाया था रेड्डी बंधु आज जेल में हैं और कर्नाटक की भाजपाई सरकार बुरी तरह चुनावी जंग हार चुकी है। फ़िर ऐसी ही व्यापक लूट करने वाले नवीन जिंदल को भी जेल के सींखचों के पीछे होना चाहिये या नहीं?

उल्लेखनीय है कि कर्नाटका में चुनावी प्रचार के दौरान सोनिया गांधी व राहुल गांधी का मुख्य तर्क होता था कि रेड्डी बंधुओं ने भाजपाई सरकार की मिली भगत से अथाह लोहा एवं कोयला चीन भेजा जो एक देशद्रोह की कार्यवाही जैसा है क्योंकि यदि लोहे को स्टील बना कर बेचा जाता और कोयले को परिष्कृत करके बिजली बनाने में लगाया जाता तो देश को अपने खनिज का सही मुनाफ़ा एवं उपयोग नसीब होता आश्चर्य है कि यही तर्क वे कांग्रेसी

नवीन जिंदल
झंडा तुम संभलो, माल हम संभालेंगे

रॉबर्ट वाड्रा
दामाद आबाद, बाकी बर्बाद

सांसद नवीन जिंदल के मामले में क्यों नहीं इस्तेमाल करते? दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान झारखंड में भाजपा या भाजपा समर्थित सरकारें ही मुख्यत: रही हैं। उनसे एक कांग्रेसी सांसद का गठजोड़ लूट की बंदरबांट से ही संभव है। आज झारखंड राज्य में राष्ट्रपति का शासन है। दूसरे शब्दों में वहां परोक्ष रूप से कांग्रेस का ही शासन है क्योंकि केन्द्र में कांग्रेस की ही सरकार है। रेड्डी बंधुओं को सीबीआई की मार्फ़त जेल का रास्ता दिखाया गया, वही सीबीआई नवीन जिंदल के खिलाफ़ जांच के लिये क्यों नहीं उतारी जा रही है?

लूट का यही तरीका नवीन जिंदल ने दूर लैटिन अमेरिकी देश बोलीविया में भी आजमाया पर 3 वर्षों में ही उसे गिरफ़्तारी के डर से सब कुछ छोड़ कर वहां से भागना पड़ा है। बोलीविया पुलिस जब तहकीकात में लगी तो जिंदल ने तेजी से अपने पैर समेटने शुरू कर दिये। उसके कर्मचारियों का अन्तिम जत्था स्थानीय पुलिस के हाथ आने से बाल-बाल ही बचा। यहां तक कि उन्हें अपने घरों व दफ़्तरों का सामान वही छोड़ कर रातों-रात निकलना पड़ा। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार बोलीविया पुलिस ने उनका ब्राज़ील तक पीछा किया और कुछ ही अन्तर से उन्हें पकड़ पाने से चूक गये।

इस बीच बोलीविया सरकार ने वहां स्थित भारतीय दूतावास को इस जालसाज़ी की पूरी सूचना भी दी है। उसी तरह स्टील प्लांट लगाने के झूठे वायदे पर बोलिविया में भी जिंदल ने लौह-अयस्क खदानें सरकार से कौड़ियों के भाव लीज पर लीं। उसी तरह खदानों से लौह अयस्त तमाम अन्य देशों को बेचा जाने लगा। उसी तरह सैकड़ों करोड़ की रकम जिंदल की जेबों में जाने लगी। भांडा तो फूटना ही था क्योंकि वहां कोई जिंदल के आकाओं का राज तो था नहीं। न वहां की पुलिस भाततीय सीबीआई की तरह है कि आका के इशारे पर किसी को पकड़ ले किसी को छोड़ दे। फ़िलहाल बोलीविया स्थित भारतीय दूतावास से वहां की पुलिस से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। पर दूतावास ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट दिल्ली विदेश मन्त्रालय को भेजी ही होगी। इसे प्रधानमंत्री व सोनिया गांधी ने देखा ही होगा। सबकी चुप्पी का एक ही राज हो सकता है कि उनके मुंह पैसे से बंद रखे गये हैं।

जी हां हम उसी नवीन जिंदल की बात कर रहे हैं जो जगह-जगह सैकड़ों फ़ीट ऊंचे राष्ट्रीय हवज लगवा कर स्वयं को सबसे बड़ा देशभक्त साबित करता फ़िरता है। उसकी असली जगह है- तिहाड़ जेल।

राबर्ट वाड्रा का मामला तो बिल्कुल ही खुला खेल है। आप एक जानी-मानी तिकड़मी रीयल एस्टेट कम्पनी से पैसे उधार लेते हैं। उस पैसे से उसी कम्पनी की प्राइम ज़मीन खरीदते हैं। आपके द्वारा ज़मीन खरीदे जाते ही राज्य सरकार उस ज़मीन का लैंड यूज़ बदल देती है। जो ज़मीन कृषि खाते की थी वह रिहायशी व व्यापारिक इस्तेमाल की बना दी गयी। ऐसा होते ही आप उस ज़मीन को वापस उसी रियल एस्टेट कम्पनी की सैंकड़ों करोड़ का मुनाफ़ा कमा कर बेच देते हैं। यह सारी कार्यवाही 2-3 महीने में पूरी हो जाती है। राज्य का एक ईमानदार अफ़सर इस जालसाज़ी में जांच शुरू करता है। राज्य सरकार उसका तबादला कर देती है। राज्य सरकार के अपने जांच अधिकारी सारे मामले को 'नियमानुसार' करार देते हैं।

आपको बेशक लगे पर यह कोई हातिमताइ का किस्सा नहीं है। आखिर सैंकड़ों करोड़ कमाने वाला कोई और नहीं देश की सबसे शक्तिशाली महिला सोनिया गांधी का दामाद राबर्ट वाड्रा जो हुआ। जिस रियल स्टेट कम्पनी का जिक्र ऊपर आया है वह रिश्वत के पायदानों पर चढ कर आज लाखों करोड़ की रियल एस्टेट की सौदागर डी एल एफ कम्पनी है। राज्य सरकार (हरियाणा) का मुखिया भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ठहरा सोनिया गांधी की कृपा पर निर्भर कांग्रेसी सल्तनत का एक जागीदार। ईमानदार अधिकारी का नाम अशोक खेमाका है। जिन अधिकारियों की जांच कमेटी ने बाद में हुड्डा के इशारे पर इस सारी जालसाज़ी को 'नियमानुसार' करार दिया वह हुड्डा की कृपा से लगे प्रशासनिक अधिकारियों का एक गिरोह है। डीएलएफ चाहता तो वह सीधे हुड्डा को रिश्वत पहुंचा कर, जैसा कि हरियाणा में आम चलन है, उपरोक्त ज़मीन का लैंड यूज़ बदलवा सकता था। पर तब रॉबर्ट वाड्रा की सैंकड़ों करोड़ की सफेद कमाई कैसे खरी होती? तब मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिह हुड्डा की गांधी परिवार के प्रति वफ़ादारी कैसे दिखती- तब डीएलएफ की हरियाणा सरकार चलाने वालों में निष्ठा कैसे प्रगट की जाती? नेशनल कैपिटल रीज़न और विशेष कर गुड़गांव में रियल एस्टेट की हज़ारों करोड़ की लूट जारी रखने के लिये डीसीएफ को और हुड्डा को अपनी निष्ठायें व वफ़ादारियां दिखाना जरुरी हो जाता है। जालसाज़ी का इतना सीधा मामला और सारे खिलाड़ी छुट्टे घूम रहे हैं। बस रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजने की देर है। षड़यन्त्र के एक-एक तार खुद-ब- खुद नंगे होते जायेंगे। कहां है सीबीआई? कहां है सुप्रीम कोर्ट? कहां है अन्ना हजारे?

-ब्यूरो

साक्षात लापता बच्चे

राहुल का बच्चा 'कौशल': बाल-श्रम बिकता रहेगा, गांधियों का ढोल बजता रहेगा

इस अंक से हम एक नया स्तंभ 'साक्षात लापता बच्चे' शुरू कर रहे है, जिसमें हर बार एक ऐसे बच्चे का विवरण होगा जो हमारी आंखों के सामने यानी 'साक्षात' है पर समाज के लिये वह 'लापता' होता है। हमारे देश में रोज़ाना सैकड़ों बच्चे गायब हो जाते हैं या गायब कर दिये जाते हैं। इनमें से बमुश्किल एक तिहाई ही वापस अपने ठिकानों पर पहुंच पाते हैं। शेष का क्या होता है? वे हमारी आंखों के सामने होते हैं पर हम उन्हें 'देख'नहीं पाते इन उत्पीड़ित बच्चों को या तो कानूनी संरक्षण की जरूरत होती है या फ़िर वे अपराधों में पड़ कर कानून से टकराव की भूमिका में पहुंच जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में बच्चे को सरकारी एवं सामाजिक दोगले पन का शिकार होना पड़ता है। सरकारों और समाजों की इस अमानवीयता को जांचने परखने और हो सके तो इस दिशा में चेतना फ़ैलाने के उद्देश्य से यह स्तंभ चलाया जाता रहेगा।

भोपाल (म.मो.) गनीमत है राहुल गांधी को साक्षात सामने खड़ा वह 10 वर्षीय लापता बच्चा नज़र आ गया। गत 25 अप्रैल को मध्यप्रदेश की राजधानी में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में राज्य स्तरीय मीटिंग सम्पन्न कर हवाई जहाज पकड़ने राजा भोज अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिये निकले चिर युवराज की गाड़ी एक लाल बत्ती पर रुकी। कौशल नामक वह 10 वर्षीय बच्चा तमाम अन्य हमउम्र बच्चों के साथ चौराहे पर रुकने वाली कारों के शीशे खटखटा कर अखबार बेच रहा था। संयोगवश कौशल ने राहुल गांधी का शीशा खटखटा दिया। युवराज के लिये यह एक अच्छा अवसर था कि वे वातानुकूलित गाड़ी में बैठे-बैठे जनता की फ़िक्र का पुण्य कमा सकें।

राहुल ने शीशा नीचे किया। मुस्कराये। अखबार लिया। जेब से हज़ार रू. का नोट निकाल कर कौशल के हाथ मे रख दिया। कौशल गिड़गिड़ाने लगा कि उसके पास इतने बड़े नोट का फुटकर नहीं है। उसे डर था कि कहीं साहब नोट वापस ले कर अखबार ही न खरीदें। वह राहुल गांधी को जाने न जाने पर राहुल गांधी मुफ़्त के प्रचार का ऐसा मौका क्यों गंवाता? इस बीच अन्य कारों के साथ चल रहे कांग्रेसी चमचों ने भी राहुल की कार के पास जमावड़ा लगा लिया था। राहुल ने बच्चे का नाम पूछा और उसे हज़ार का नोट रखने दिया।

राहुल तो अपने रास्ते चले गये। पर स्थानीय कांग्रेसियों के लिये काम छोड़ गये। कुछ दिनों तक भोपाल के कांग्रेसियों में यह विमर्श चलता रहा कि कैसे इस घटना को एक जनकल्याणकारी प्रसंग बना कर भुनाया जाये? यह डर भी था कि कहीं जो किया वह युवराज के नज़रिये से ठीक नहीं बैठा तो मुश्किल हो सकती है। लिहाज़ा बाकायदा दिल्ली दरबार से हरी झंडी ली गयी। 11 मई को भोपाल स्थित काग्रेस के राज्य कार्यालय में कौशल और उसयके पिता की मीडिया के समक्ष परेड कराई गयी। कौशल के पिता अनियमित दिहाड़ी मज़दूर हैं और उनकी आजीविका प्राय: डांवाडोल ही रहती है। इसी लिये कौशल को चौराहों पर अखबार बेच कर कुछ पैसा कमाना होता है। कांग्रेसियों ने इस अवसर पर दो घोषणायें कीं। पिता को स्थानीय राजीव गांधी महाविद्यालय जो एक कांग्रेसी नेता की सम्पत्ति है, में चपरासी

की नौकरी दी जायेगी। साथ ही बालक कौशल को आगे पढ़ने-लिखने के लिये प्रति माह एक हज़ार रू. दिये जायेंगे। अगले दिन अखबारों व अन्य मीडिया में इस अवसर की फ़ोटो व उक्त घोषणायें व्यापक रूप से प्रसारित की गयीं।

जो सवाल उपरोक्त प्रसंग से निकलते हैंऔर जिन्हें न कांग्रेसियों ने, न विपक्षियों ने और न मीडिया ने उठाया, वे इस प्रकार हैं-

1. 14 वर्ष से कम उम्र का बाल-श्रम कानूनन दंडनीय अपराध है। ऐसा श्रम कराने वाले व उसे प्रोत्साहित करने वाले अपराधी हैं। इस तरह, कौशल व तमाम अन्य हमउम्र बच्चों से श्रम कराने वाले ही नहीं बल्कि लाल बत्ती चौराहे पर प्रोत्साहित करने वाले राहुल गांधी व उनके चमचे भी अपराधी हो जाते हैं।

2. भोपाल में प्रमुख राष्ट्रीय विपक्षी दल भाजपा की सरकार है उनके तमाम महकमों का काम ऐसे बाल श्रमिकों के पुर्नवास एवं शिक्षा की व्यवस्था करना है। ऐन राजधानी की मुख्य सड़क पर जब सरेआम बच्चे चौराहों पर अपनी विवशता बेच रहे हैं तो क्या समूची राज्य सरकार को कठघरे में नहीं खड़ा करना चाहिये? पर कांग्रेसी भी चुप रहे क्योंकि ये 'लापता' बच्चे उन्हें इस नज़रिये से तो नज़र आ नहीं सकते।

3. एक कौशल को तो राहुल गांधी के इशारे पर वज़ीफ़ा मिल गया, उसके पिता को नौकरी का वायदा भी, पर भापाल शहर ही वैसे हज़रों कौशलों को क्या कोई उत्पीड़न से राहत की उम्मीद हो सकती है? प्रदेश में तो ऐसे लाखों 'कौशल' होंगे और देश में करोड़ो। कांग्रेस, भाजपा ही नहीं तमाम राजनीतिक दलों के लिये वे 'लापता' ही रहते हैं।

4. हर बालश्रमिक अपने माता-पिता की बेरोज़गारी की उपज होता है। यदि वयस्कों को सही रोज़गार उपलब्ध हो तो बच्चों को बाल-श्रम के उत्पीड़न भरे चक्र में पड़ने की नौबत ही न आये। रोज़गार के मसले का न कांग्रेसियों के पास कोई हल है, न भाजपाइयों के, न तमाम राजनैतिक दलों के। और न ही इस सम्पूर्ण पूंजीवादी व्यवस्था के पास ऐसा कोई रास्ता है जो तमाम तकनीकी एवं आर्थिक प्रगति के बावजूद सभी को रोज़गार के अवसर दिला सके।

5. तो क्या 'लापता' बच्चे भी साक्षात बने रहेंगे और राहुल गाधियों की जनकल्याण के ढोल भी यूं ही पीटे जाते रहें गे?